विश्व स्तनपान सप्ताह (१–७ अगस्त, २०१२)

नीतियों एवं योजनाओं की समीक्षा

BREASTFEEDING SAVES LIVES
BPNI

IBFAN ASIA

बच्चों को चाहिए
प्राकृतिक आहार
कृत्रिम नहीं ।

BPNI 2012

विश्व स्तनपान सप्ताह–2012
नीतियों एवं योजनाओं की समीक्षा

20 वर्ष पहले विश्व तथा हिन्दुस्तान में पहली बार यह सप्ताह मनाया गया था। पहली थीम थी ''बेबी फ्रेंडली हास्पिटल इनीशिटिव (BFHI)''। आज फिर खुशियाँ मनाने का समय है, परन्तु यह भी देखना है कि इन 20 वर्षों में क्या बदला है और क्या और करने की जरूरत है। हर साल हम एक नई थीम के साथ सप्ताह मनाते रहे हैं। इस वर्ष हमने पिछले 20 वर्षों की नीतियों तथा योजनाओं की समीक्षा करने का निश्चय किया है। इसके लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

- स्तनपान एवं शिशुओं तथा छोटे बच्चों के पोषण कार्यक्रम (IYCF) की योजनाओं के कार्यान्वन की समीक्षा।
- पिछले 20 वर्षों की सफलताओं एवं उपलब्धियों की खुशी मनाना।
- जो कमियाँ रह गयी हैं, उन्हें ढूढना तथा उन्हें ठीक करना।
- जनता तथा नीति निर्धारकों को इन कमियों के बारे में जागरूक करना।
- अपने कार्यों की जानकारी राश्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को देना।

बीसवीं शताब्दी में स्तनपान के अनेक विकल्प उपलब्ध हो गये तथा उनको बेचने के लिए बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने आक्रामक मुहिम चलायी। इससे स्तनपान में गिरावट आई। स्वास्थ्य सेवाओं से अपेक्षित सहयोग न मिलना, सामाजिक वर्जनाएँ, सांस्कृतिक बाधाएँ तथा स्त्रियों का नौकरी करना अन्य कारण हैं। डिब्बा बन्द दूध बनाने वाली कम्पनियों के शातिराना प्रचार के तरीकों ने मानव जाति की स्तनपान तथा भोजन सम्बन्धी परम्परागत तरीकों को तहस–नहस कर दिया जिससे लोगों का प्राकृतिक आहार (स्तनपान एवं घरेलू भोजन) से विश्वास उठ गया और वे फैक्ट्री में बने डिब्बा बन्द आहार को बेहतर समझने लगे। इस खतरनाक तथा शिशुओं के लिए जानलेवा भ्रान्ति को तोड़ने की जरूरत है। इस युद्ध में जनता को जीतना ही है क्योंकि झूठ सिर्फ चन्द दिनों का मेहमान होता है।

बच्चों को चाहिए
प्राकृतिक आहार
कृत्रिम नहीं।

नीतियों एवं योजनाओं की समीक्षा करने की जरूरत क्यों है?

भारतवर्ष में 1992 से स्तनपान सम्बन्धी ऑकड़े इकट्ठा किये जाने लगे और पिछले 20 वर्षों से एक अपवाद को छोड़कर उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। सिर्फ जन्म के एक घण्टे में स्तनपान करवाने वाली माताओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गयी है।

बाकी दो ऑकड़े यानि 6 माह तक केवल स्तनपान (Exclusive Breastfeeding for six months) तथा 6 माह बाद स्तनपान के साथ–साथ अनुपूरक आहार देने का ऑकड़ा यथावत है। हॉ यह जरूर संभव है कि हम सबके प्रयत्नों से ऑकड़ों में गिरावट नहीं हो रही है जैसा 1970 और 80 के दशक में हुआ था।

भारत सरकार ने स्तनपान तथा शिशुओं एवं छोटे बच्चों में पोषण सम्बन्धी तरीको में बदलाव के लिए बहुत सारे कदम उठाये हैं। संदर्भ– Infant Milk Substitutes feeding bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 and Amendment 2003 (IMS Act) & National Guidelines on Infant and Young Child Feeding (2004) and updated in 2006.

इसके बावजूद बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत सरकार ने मातृत्व अवकाश को सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 से बढ़ाकर 6 माह कर दिया है तथा तमाम राज्य सरकारों ने भी इसे लागू कर दिया है। इसके अलावा 2 साल तक चाइल्ड केयर लीव भी ली जा सकती है। निजी क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए एक नगद सहायता राशि कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया है। (जननी सुरक्षा योजना)

हमें देखना चाहिए कि उपरोक्त कानूनों को लागू करने में हम कितना आगे बढ़े है और यह भी देखना है कि डिब्बा बन्द आहार बनाने वाली कम्पनियॉ किस तरह इस कानूनों से खिलवाड़ कर रही हैं ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

यह कार्य कौन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जैसे–सिविल सोसाइटी ग्रुप, स्तनपान के पक्षधर लोग, चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोग, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि, यह कार्य कर सकते हैं। डिब्बा बन्द दूध बनाने वाली कम्पनियों तथा उनके सहयोगी संस्थानों को IMS कानून का पालन करना चाहिए और स्वास्थ्य कर्मियों तथा माताओं को लालच या गलत जानकारी देकर अपना सामान नहीं बेचना चाहिए। सरकारों को डिब्बा बन्द दूध एवं आहार के प्रचार के गलत तौर तरीकों को रोकना चाहिए तथा माताओं की रक्षा एवं सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक मॉ को जरूरत पड़ने में प्रशिक्षित कार्यकर्ता की मदद मिलनी चाहिए तथा हर एक मॉ को मातृत्व अवकाश तथा अन्य सुविधाऍ मिलनी चाहिए। हम सब भी इनमें से किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं।

अनुवादक– डॉ0 बी0बी0 गुप्ता, जिला समन्वयक, बीपीएनआईए शाखा–गोरखपुर (उ0प्र0)